

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2021—श्रावण 11, शक 1943

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2021

क्र. 1036-183-2018-ए-सोलह.—बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जनवरी 2021 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

### “संशोधन”

उक्त नियमों में,—

1. नियम 1 में, उप-नियम (1) में, शब्द “बाल श्रम” के स्थान पर शब्द “बालक और कुमार श्रम” शब्द स्थापित किए जाएं;

2. नियम 2 में,—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 (1986 का 61).

(2) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(घक) “निधि” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 ख की उप-धारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार पुनर्वास निधि;

(घघ) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक;

(घघ) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्व-शासन की कोई संस्था;

(घघ) "पंचायत" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित पंचायत.

(3) नियम 2 के खण्ड (च) में शब्द 'युवा व्यक्ति', के स्थान पर, शब्द 'कुमार' तथा शब्द "कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), के स्थान पर, शब्द "बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35)" स्थापित किये जाएं।

(4) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जाये अर्थात्:—

"(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, और अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित किये गये हैं।

3. नियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"2क. अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध पर जागरूकता—राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए, कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,—

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया का उपयोग सम्मिलित है ताकि जनसाधारण जिसके अंतर्गत नियोजक तथा बालक और कुमार जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो सम्मिलित है को अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूक किया जाए तथा जिसके द्वारा नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या कुमारों के नियोजन के उपक्रम या घटनाओं की रिपोर्टिंग को, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से संपर्क के आसानी से उपलब्ध साधनों को विकसित तथा विज्ञापित करके, बढ़ावा देगी;

(ग) अधिनियम, इन नियमों के उपबंधों और उनसे संबंधित किसी अन्य सूचना का संभव सीमा तक मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजा, अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, बाजार, सिनेमा हाल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय सम्मिलित है, में प्रदर्शन करेगी;

(घ) समुचित माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में अधिनियम के उपबंधों के समावेश को बढ़ावा देगी; और

(ङ) प्रशिक्षण को समावेश करने और अधिनियम के उपबंधों पर संग्राह सामग्री तथा पुलिस, न्यायिक तथा सिविल सेवा अकादमियों, शिक्षक प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में इसके अतिरिक्त विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देगी तथा अन्य सुसंगत हितधारकों, जिसमें पंचायत सदस्य, चिकित्सक तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी सम्मिलित है, के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी।

**2ख.** बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना अपने परिवार की सहायता करना।—(1) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालयीन शिक्षा को प्रभावित किए बिना,—

(क) अपने परिवार के उद्यम में अपने परिवार की इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा, कि ऐसी सहायता,—

(एक) अधिनियम की अनुसूची के भाग के एवं भाग ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी;

(दो) विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा त्रृत्यला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके परिवार या परिवार के उद्यम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;

(तीन) उसके परिवार या परिवार उद्यम सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां परिवार अधिभोगी हैं;

(चार) वह विद्यालय समय के दौरान और सायं 7 बजे और प्रातः 8 बजे के बीच कोई कार्य नहीं करेगा;

(पांच) वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए उसकी शिक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई हैं;

(छह) बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;

(सात) किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके परिवार या परिवार के उद्यम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है; और

(आठ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी;

(छ) अपने परिवार की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए हानिकारक नहीं है.

**स्पष्टीकरण 1.** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल—

(क) बालक का सगा भाई और बहन;

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन; और

(ग) बालक के माता-पिता के सगे भाई और बहन, को बालक के परिवार में सम्मिलित किया जाएगा.

**स्पष्टीकरण 2.**—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच कर के दूर किया जा सकेगा.

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्राचार्य या प्रधानाध्यापक सूचना के लिए

ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (एक) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

#### 2ग. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना।—

(1) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घंटे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों से अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित हैं, का निर्माता बालक की सहभागिता को केवल उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्ररूप 'ग' में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्कीनिंग इस डिस्क्लेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरुपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो के लिए सभी उपाय किए गए हैं;
- (ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुरूप बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत—
  - (एक) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना;
  - (दो) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;
  - (तीन) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आप्रय; और
  - (चार) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी विधियों का अनुपालन, को सम्मिलित करते हुए उनकी शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार;
- (घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किए जा सकें;
- (च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत् को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा; और
- (छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप को सम्मिलित करते हुए में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- (2) धारा 3 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट “अन्य ऐसा कार्यकलाप” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा—
- (एक) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में स्वयं भाग ले रहा है;

(दो) रियलटीशो, किंवज शो, टेलेंट शो को सम्मिलित करते हुए दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंट्री प्रदर्शन, रेडियो तथा किसी कोई अन्य माध्यम है;

(तीन) नाटक, सीरियल;

(चार) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और

(पांच) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे राज्य सरकार विशिष्ट मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत, धनीय फायदे के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं हैं।

4. नियम 3 में, उप-नियम (1) में, शब्द “बालक श्रम” के स्थान पर, शब्द “बालक और कुमार श्रम” स्थापित किए जाएं।

5. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“4. आयु का प्रमाण-पत्र.—

(1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिष्ठित है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय:—

(एक) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(दो) विद्यालय से जन्म की तारीख का प्रमाण-पत्र या, कुमार से संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(तीन) निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार का जन्म प्रमाण-पत्र पर विचार करेगा; और खंड (एक) से खंड (तीन) में, विनिर्दिष्ट रीति के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण श्रम आयुक्त से अनिम्न पदश्रेणी के समुचित प्राधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पद्धति दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु का प्रमाण-पत्र प्ररूप “ख” में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वही होंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

**स्पष्टीकरण:**—इस नियम के प्रयोजन के लिए,—

(एक) “चिकित्सा प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा कोई सरकारी, चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक से अनिम्न पदश्रेणी का न हो या कर्मचारी राज्य बोर्ड औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक;

(दो) “कुमार” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खंड (एक) में यथा परिभाषित कुमार.”।

6. नियम 4 जो पश्चात्, निम्नलिखित नियम, अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“4क. कार्य के घंटे—धारा 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उत्तरे घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने कि ऐसी स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञय है।

**5. बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में से रकम का संदाय.—**

(1) धारा 14 ख की उप-धारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उद्भूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसी रकम का प्रत्यय किया गया है; अर्थात्—

- (एक) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला गया है और, उस बैंक को सूचित करेगा जिसमें निधि की रकम को जमा की गयी है यथास्थिति, धारा 14 ख की उप-धारा (3) के अधीन निधि की रकम का विनिधान करने के लिए अधिकारी उत्तरदायी होगा;
- (दो) बालक या कुमार के पक्ष में निधि की समानुपाती रकम पर उद्भूत ब्याज को निरीक्षक की जानकारी के अधीन बैंक या रकम का विनिधान करने वाले उत्तरदायी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में प्रत्येक छह माह में अंतरित किया जाएगा;
- (तीन) अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तब, यथासंभव शीघ्र तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उद्भूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14 ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, यथास्थिति, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अंतरित की जाएगी; और
- (चार) निरीक्षक संबंधित बालक या कुमार की उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त विशिष्टियों, के साथ खंड (दो) और खंड (तीन) के अधीन अंतरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ श्रम आयुक्त की जानकारी के लिए भेजेगा.

(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुमानि के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

**6. वह व्यक्ति जो परिवाद दर्ज कर सकता है।—कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद दायर कर सकेगा जिसमें सम्मिलित है विद्यालय के शिक्षक तथा विद्यालय प्रबंध समिति के प्रतिनिधि, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका, जो उस दशा में, परिवाद दायर करने के लिए संवेदनशील होगा कि उसके अपने-अपने विद्यालय के छात्रों में से कोई इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया जाता है।**

**7. अपराधों के शमन करने की रीति।—(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,—**

- (एक) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या
- (दो) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,

धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबंधित निरीक्षक को सुनवाई के पश्चात्, आवेदन का निपटारा करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए प्रशमन करने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा—

- (एक) ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुमानि के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या
- (दो) खंड (एक) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुमानि के पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन प्रशमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो, कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

#### 8. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य—(1) जिला मजिस्ट्रेट—

(एक) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे;

(दो) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

(तीन) किसी जिले में निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;

(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (एक) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;

(ड) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार श्रम कार्यालय का जिला या संभागीय कार्यालय प्रमुख;

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो प्रतिनिधि;

(छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;

(ज) जिले की एन्टीट्रेफिकिंग यूनिट का एक सदस्य;

(झ) जिले की बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष;

(ज) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण योजना के अधीन जिले में जिला बाल संरक्षण अधिकारी;

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी;

(ठ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का परियोजना निदेशक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;

(ड) कार्य बाल का सचिव खंड (एक) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उप-नियम (1) के खंड (तीन में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर श्रम आयुक्त द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें—

- (क) निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जाएगा
- (एक) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (दो) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);
- (तीन) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेवर स्कीम, 2106;
- (चार) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना ;
- (पांच) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या योजना, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीन—

  - (क) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हो;
  - (ख) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या श्रम आयुक्त द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

**9. निरीक्षकों के कर्तव्य।—**धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए—

- (एक) राज्य सरकार या श्रम आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;
- (दो) राज्य सरकार या श्रम आयुक्त द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और
- (तीन) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में श्रम आयुक्त को मासिक रिपोर्ट करेगा।

**10. आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना—**राज्य सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(एक) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालित किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन स्थानों पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं;

(दो) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक श्रम आयुक्त को खंड (एक) के अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;

(तीन) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना—

(क) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम के उल्लंघन में परिवार या परिवार उद्यमों में लगे हुए पाए जाते हैं;

(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे ; और

(घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशारों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे.”.

8. प्ररूप क में, शब्द “बालक का नाम” के स्थान पर, “बालक और कुमार” शब्द रखे जाएं।

9. प्ररूप ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्रारूप ग”

[नियम 2 ग (1) (ख) (1) देखिए]

**बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम 1993**

मैं ..... निर्माता ..... का श्रव्य-दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण  
या आयोजक ..... वाणिज्यिक आयोजन का निर्माता हूं जिसमें निम्नलिखित बच्चा/बच्चे भाग ले रहे  
हैं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	बालक/बालकों के नाम	माता पिता/संरक्षक का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)

एतद्वारा यह बचन देता हूं कि ..... आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करे) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) और मध्यप्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 2018 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा ध्यान रखा ताकि वह/उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी बचन देता हूं कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिये तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

तारीख .....

No. 1036-183-2018-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1993, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra-Ordinary) dated 8th January, 2021 as required by sub-section (1) of Section 18 of the said Act, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Child Labour", the words "Child and Adolescent Labour" shall be substituted;

(2) in Rule 2,—

(1) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) 'Act' means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986);

(2) After clause (d), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(da) 'Fund' means the Child and Adolescent Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of Section 14B of the Act;

(db) 'Inspector' means the Inspector appointed by the State Government under section 17;

(dc) 'Municipality' means an institution of self Government constituted under article 243 Q of the Constitution;

(dd) 'Panchayat' means a Panchayat constituted under article 243B of the Constitution";

(3) In clause (f) of rule 2, for the words "Young Person", the word 'Adolescent' and for the words "the Factories Act (No. 63 of 1948)", the words "the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (No 35 of 2016)" shall be substituted.

(4) After clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

“(g) words and expressions used in these rules, but not defined therein and defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.”.

3. After rule 2, the following rules shall be inserted, namely:—

**“2A. Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in contravention to Act.—**

The State Government, to ensure that the children and adolescents are not loyed or Permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures, shall.-

(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;

(b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the State Government;

- . (c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in major bus stations, toll plazas and other public places including shopping centres, markets, cinema halls, hotels, hospitals, panchayat offices, police stations, industrial areas, schools, educational institutions, court complexes, and offices of all authorities authorised under the Act;
- (d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; and
- (e) promote inclusion of training and sensitisation material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in police, judicial and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitisation programmes for other relevant stakeholders including panchayat members, doctors and concerned officials of State Government.

**2B. Child to help his family without affecting education.-**

- (1) Subject to the provisions of Section 3, a child may, without affecting his school education, in any manner,-
  - (a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help,-
    - (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and Part B of the Schedule to the Act;
    - (ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing, production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;
    - (iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where his family is the occupier;
    - (iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8. a.m.;
    - (v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;
    - (vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;
    - (vii) shall not include in any way substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; and
    - (viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force;
  - (b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth education and overall development of the child.

**Explanation 1.-** For the purposes of this rule, only—

- (a) biological brother and sister of the child;
- (b) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; and
- (c) biological brother and sister of parents of the child,

shall be included for comprising the family of a child.

**Explanation 2.-** For the purposes of Explanation 1, it is hereby clarified that preliminarily, any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, may be removed by examining the pedigree of such person issued by the concerned Municipality or Panchayat, as the case may be, or any other legal document issued by concerned authority of the State Government.

2. Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 8 for information.

### **2C. Child to work as an artist.-**

- (1) Subject to the provisions of Section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely :—
  - (a) No child shall be allowed to work for more than five hours in a day, and for not more than three hours without rest;
  - (b) Any producer of any audio-visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants, consent of parents or guardian, as the case may be, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child, and ensure that all screening of this films and television programmes shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in the shooting, then, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting;
  - (c) The undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the State Government from time to time for such purpose including—
    - (i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;
    - (ii) timely nutritional diet of the child;
    - (iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; and
    - (iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences;
  - (d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and on child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days;
  - (e) one responsible person be appointed for maximum of five children for the production or event, so as to ensure the protection, care and best interest of the child;
  - (f) at least twenty per cent, of the income earned by the child from the production of event to be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalised bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority; and
  - (g) no child shall be made to participate in any audio visual and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent.

(2) For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub-section (2) of section 3, the expression “such other activity” contained therein, shall mean—

- (i) any activity where the child himself is participating in a sports competition or event or training for such sports competition or event;
- (ii) cinema any documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows, radio and any programme in or any other media;
- (iii) drama serials;
- (iv) participation as anchor of a show or events; and
- (v) any other artistice performances which the State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.”.

4. In rule 3, in sub-rule (1), for the words “Child Labour”, the words “Child and adolescent Labour” shall be substituted.

5. For rule 4, the following rules shall be substituted, namely :-

**"4. Certificate of age.—**

- (1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority;
- (2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account—
  - (i) The Aadhar card of the adolescent, and in the absence thereof;
  - (ii) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;
  - (iii) the birth certificate of the adolescent given by a Corporation or a Municipal Authority or a Panchayat;

and only in the absence of any of the methods specified in clauses (i) to (iii), the age shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.
- (3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority not below the rank of Labour Commissioner, as may be specified by the State Government in this behalf, and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.
- (4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B.
- (5) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the State Government for their Medical Boards.
- (6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.

**Explanation:** For the purposes of this rule,-

(i) “medical authority” means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees State insurance dispensaries or hospitals;

(ii) “adolescent” means an adolescent as defined in clause (i) of Section 2 of the Act.

6. After rule 4, the following rules shall be inserted, namely :-

**“4A. Hours of Work.-** Subject to the provisions of Section 7, no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.

**5. Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.-**

(1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely :-

(i) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalized bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of Section 14B;

(ii) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;

(iii) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of Section 14B, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and

(iv) the inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iii) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the labour Commissioner for information.

(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgment of a Court in favour of a child or adolescent for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgment.

6. **Persons who may file complaint .—** Any person may file a complaint under the Act for commission of any offence include school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, panchayat or municipality, who shall be sensitised to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act.

**7. Manner of compounding of offences.-**

- (1) An accused person,-
  - (i) who commits an offence for the first time under sub-section (3) of Section 14; or
  - (ii) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section; may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of Section 14D.
- (2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the inspector concerned on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to-
  - (i) the payment of a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or
  - (ii) the payment of an additional sum of twenty-five percent of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified period, and such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate, which shall not exceed the period specified in that clause.
- (3) The Compounding amount shall be paid by the accused person to the State Government.
- (4) if the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of Section 14D.

**8. Duties of District magistrate.-** (1) The District Magistrate shall-

- (i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called nodal officers nominated as such by the Labour Commissioner, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the State government under Section 17A;
- (ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer;
- (iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in a district consisting of—
  - (a) inspector appointed under Section 17 for the purposes of his local limits of jurisdiction, as nominated by the District Magistrate;
  - (b) Superintendent of Police for the purposes of his local limits of jurisdiction;
  - (c) Additional District Magistrate for the purposes of his local limits of jurisdiction;
  - (d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes of his local limits of jurisdiction;
  - (e) Head of the office of District or Divisional Labour office of the State Government for the purposes of his local limits of jurisdiction;
  - (f) two representatives each from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years;
  - (g) a representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge;

- (h) a member of the District Anti-trafficking Unit;
- (i) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District;
- (j) District Child Protection Officer in the District under the integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with Women and Child development.;
- (k) District Education Officer;
- (l) Project Director of National child Labour Project or any other person nominated by the District magistrate;
- (m) Secretary of the Task Force shall be any of the nodal officers referred to in clause (i) and nominated by the Chairperson.

(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in two months and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the Labour Commissioner from time to time, and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the Central Government.

(3) In addition to the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated-

- (a) in accordance with the provisions of-
  - (i) the Juvenile justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 (2 of 2016) and the rules made thereunder;
  - (ii) the Bonded Labour, System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976);
  - (iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016;
  - (iv) any National Child Labour Project;
  - (v) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated and subject to.—
    - (i) the directions, If any of a court of competent Jurisdiction ;
    - (ii) the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central Government or State Government or Labour Commissioner from time to time in this regard.

9. **Duties of Inspectors.**—An Inspector appointed by the State Government under Section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall—

- (i) comply with the norms of inspection issued by the State Government or Labour Commissioner from time to time,
- (ii) comply with the instructions issued by the State Government Or Labour commissioner from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and
- (iii) report to the Labour commissioner monthly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by

him for such purposes.

10. **Periodical inspection and monitoring.**—The State Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying into effect the provisions of Section 17, which may include—

- (i) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or Processes are carried out;
- (ii) the intervals at which an inspector shall report to the Labour Commissioner complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (i) and the details of action taken by him thereafter;
- (iii) maintenance of record electronically or otherwise of—
  - (a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act;
  - (b) number and details of the offences compounded;
  - (c) details of compounding amount imposed and recovered; and
  - (d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.”.

8. In Form-A, in column (2), for the words “Name of child” the words “Name of child or adolescent” shall be substituted.

9. After Form-B, the following Form shall be inserted, namely:—

**“Form C”**

[See Rule 2C (1) (b)1]

Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1993

I ..... producer of ..... an audio visual media production or organiser of ..... a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely—

S.No (1)	Name of the child/children (2)	Parents/Guardian's Name (3)	Address (4)
-------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

do hear by undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child /children in the event ..... (specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and the Madhya Pradesh Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2018 and full care shall be taken of the physical and mental health and other requirements of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied.

Date .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छोटे सिंह, उपसचिव.